

262
प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या: 1335 / VII-1/63-ख/2014

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग विभाग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 11 अगस्त, 2016

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आयोजनागत पक्ष की योजनाओं में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-120/लेखा/बजट/आयोजनेत्तर-आयोजनागत/2016-17 दिनांक 25 अप्रैल, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में अनुदान सं० 23 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की खनन प्रशासन का अधिष्ठान योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष ₹ 1667 हजार (₹ सोलह लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न विवरणानुसार प्रदिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	लेखावर्षिक/योजना/मद का नाम	(धनराशि ₹ हजार में)
		स्वीकृत धनराशि
1.	2853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन (लघु शीर्षक 003 के स्थान पर)- 03-खनन प्रशासन का अधिष्ठान 29-अनुरक्षण	1667
	योग	1667

- (1) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०-8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक कदापि व्यय नहीं को जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
- (4) धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिकों के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (5) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (6) अनुरक्षण कार्य करने से पूर्व नेगमानुसार आगणनों का गठन कर सक्षम स्तर से स्वीकृति आवश्यक प्राप्त की जाय।
- (7) शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-2853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन (लघु शीर्षक 003 के स्थान पर)-03-खनन प्रशासन का अधिष्ठान-29-अनुस्क्षण के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-355/XXVII-2/2016 दिनांक 30 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या-1335 (1)/VII-1/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, आबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ✓ 7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव